



2026:AHC:167552

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7868

वर्ष 2026

ऋतु सिंह

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमर सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. मैंने आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से आपराधिक वाद संख्या 31/2026, आयुध अधिनियम की धारा 25, जफराबाद पुलिस थाना, जौनपुर जिला, में अग्रिम जमानत पाने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आवेदक एक महिला है। यह भी कहा गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर आवेदक की बदली हुई फोटो डाल दी थी। असल में, आवेदक ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड नहीं की है। आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



के तहत आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक जाँच और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देती है और जाँच अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगी। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम जमानत मिलती है, तो वह जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेगी, जाँच में सहयोग करेगी और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगी।

4. दूसरी ओर, एजीए ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, वे तथ्यों से इनकार नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने और अभिलेख देखा।

6. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत देने के प्रार्थना-पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सख्यों के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना शामिल है, की संभावना और न्याय से भागने की संभावना, जैसे देश छोड़कर भागना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना-पत्र देने वाले की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जमानत देना है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676** मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक आदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जांच के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में लेकर पूछताछ करना ज़रूरी हो, या अपराध बहुत गंभीर हो, या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के भागने का डर हो। सिर्फ इसलिए कि गिरफ्तारी करना विधिक रूप से सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति होने और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को एक सामान्य प्रक्रिया बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अगर जांच अधिकारी के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और आरोपी ने वास्तव में जांच में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम ज़मानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, प्रार्थना-पत्र देने वाले की भूमिका और मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत के लिए मामला बनता है।

9. इसलिए, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना-पत्र को इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर इस मामले में शामिल आवेदक-रितु सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित पुलिस थाने के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानती देने होंगे;

(ii) आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेंगी और जांच के मकसद से ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होंगी;

(iii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देंगी, जिससे वे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी जानकारी देने से रुकें; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।

10. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, सरकारी अधिवक्ता/जांच अधिकारी/शिकायतकर्ता को संबंधित न्यायालय में आवेदक को दी गई अग्रिम ज़मानत निरस्त करने के लिए उचित प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

11 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।